

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-57
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर

†57. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्र सरकार द्वारा देश में यूपीएससी परीक्षा के लिए कितने कोचिंग सेंटर अधिकृत हैं;
- (ख) यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा अनधिकृत कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध वर्षवार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को कोचिंग संस्थानों के मामले में सक्रिय कार्रवाई करने की आवश्यकता है। निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने हेतु, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिशानिर्देश/विनियम/विधियों को तैयार किया है। देशभर में फैले ये कोचिंग केंद्र अधिकांशतः व्यावसायिक इकाइयां हैं जिन्हें संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नियमानुसार विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्रालय ने भी दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग नाम से एक योजना चलाता है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा सहित

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरियां प्राप्त करने और/या प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना है। यह योजना डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। आज की तिथि की स्थिति के अनुसार, कुल 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और महिलाओं को विशेष कोचिंग के माध्यम से समान अवसर प्रदान करके उनकी सहायता के लिए वर्ष 2009 में आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) योजना शुरू की गई थी। चयनित केंद्रीय विश्वविद्यालयों—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), जामिया हमदर्द और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय—में शुरू की गई यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें केंद्र/राज्य सरकार की सेवाएं, बैंकिंग और निजी क्षेत्र की नौकरियां शामिल हैं, के लिए आवासीय कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मामूली पंजीकरण और छात्रावास शुल्क लिया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए कोचिंग संस्थानों पर दंड भी लगाया है और उन्हें ऐसे विज्ञापनों को रोकने हेतु निदेश भी देता है।
